आयोग में रिक्त पदों को भरने के प्रश्न पर सरकार अत्याधिक ध्यान दे रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का नामांकन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31-1-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि की अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ।

(घ) वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 1-1-1992 से 31-1-1993 तक किए गए विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा दिया गया है । आयोग ने महिलाओं से संबंधित कुछ कानूनों तथा विधानों का विस्तृत अध्ययन किया है तथा उनमें कई संशोधनों की सिफारिश की है । रिपोर्ट में आयोग ने दहेज निषेध अधिनियम, सती निवारण अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, अवयस्क बच्चों के क्रय एवं विक्रय संबंधी प्रावधानों, महिलाओं पर अत्याचार की रोकथाम हेतु उपयुक्त निकायों के सृजन तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्तर में सुधार करने के लिए उन्हें रोजगार उपलब्ध करने के विशेष प्रयास करने हेतु कई संशोधनों की सिफारिश की है ।

[nstiontions for Foreign Students

4966. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, be, pleased to, state;

(a) whether Government have set up a committee to study the feasibility of throwing open select institutions of higher learning to foreign students;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(c) the effect of the scheme on the availability of seats to Indians?

THE DEPUTY MINISTER IN THE 'MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION & DEPTT. OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) to (c) According to the information furnished by UGC the Commission has set up a Committee, comprising eminent academicians and educational administrators, to work, out modalities for providing educational opportunities to foreign students as also to generate resources for higher education. The Committee has not yet finalised its recommendations.

स्कूलों को दी गई सुविधायें

4967. श्री अन्नतराम जायसवाल
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में 5 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग के कितने बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में कितने प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पेयजल और मूत्रालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे कितने स्कूल हैं जिनकी न तो अपनी इमारत है और न ही खेल का मैदान है ;

(घ) दोनों आयु वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के कुल कितने-कितने बच्चों को पिछले वर्ष प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में दाखिल किया गया है तथा उनमें से कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 50 प्रतिशत छात्र प्राथमिक और मिडिल स्तर के शिक्षा सत्र के बीच में या उसके समाप्त होने पर पढ़ना छोड़ देते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित पांचवे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, देश की 94.5% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय तथा 83.98% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 3 किलोमीटर की पैदल दूरी वाले क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना जो कि एक प्रकाशित दस्तावेज है, इसी सर्वेक्षण रिपोर्ट में है तथा यह संसद भवन की लाइब्रेरी में उपलब्ध है ।

(घ) वर्ष 1993–94 के दौरान, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त नामांकन क्रमशः लगभग 28 3 लाख तथा 12.06 लाख था ।

(ङ) वर्ष 1993–94 के दौरान कक्षा I से V तथा कक्षा I से VIII के पढ़ाई बीच में छोडकर जाने वाले छात्रों की दर क्रमशः 36 32% तथा 52.80% थी ।

बच्चे कई कारणों से पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं, मुख्यतः ये कारण सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक प्रवृत्ति के होते हैं।

महिलाओं के लिए साक्षरता कार्यक्रम

4968. प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 24 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1803 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं के लिये साक्षरता कार्यक्रम में जनसंख्या अध्ययन को समाविष्ट करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है । इसमें छोटे परिवार के आदर्श की व्यावहारिक जागरूकता शामिल है । चूंकि साक्षरता कार्यक्रमों मे महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य समूह के रूप में सम्मिलित किया जाता है, अत वातावरण तयार करने, प्रशिक्षण सामग्रियों, प्रशिक्षण-अध्ययन इत्यादि जसे चल रहे साक्षरता अभियानों के विभिन्न चरणों के माध्यम से महिलाओं में जनसंख्या विषयों से संबंधित देश प्रसारित किए जा रहे हैं ।

Setting op UPS in different States .

4969. SHRI SARADA MOH-ANTY; Will the Minister of HU MAN RESOURCE DEVELOP MENT be pleased to state:

(a) the states where, Indian lnsti tute of Technology, (IIT) have not been set up;

(b) whether Orissa is one such State where IIT has not been set up;

(c) whether Government propose to set up IIT's in the States where, no such institute is set up; and..

(d) if so, by when and the steps taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KM. SELJA): (a) and (b) The , Indian. Institutes of Technology are not set up State-wise. There are six In- dian Institutes of Technology locat. ed at Kharagpur (West Bengal), Bombay (Maharashtra), Kanpur,,. (Uttar Pradesh). Madras (Tamil-' nadu), Delhi and Guwahati (Assam).

(c) and (d) There is no proposal to set up mere Indian Institutes of Technology in the country.

देश के पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा का निम्न स्तर

4970. श्री महेश्वर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की